

प्रेषक,

एस0 राजू  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,  
उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम,  
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून: दिनांक- २५ अगस्त २०१०

विषय:-यूयूएसडीआईपी के लिए गठित आईपीएमयू के कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17-10-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयनुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, देहरादून के पत्र संख्या PD(ADB)/(09-10) F-12(II)/476 दिनांक 2-7-2009 द्वारा शासनादेश संख्या 1506/IV(2)-श0वि0-08-38(सा0)/07 दिनांक 24-11-2008 द्वारा आई०पी०एम०यू० के लिए अस्थाई रूप से सृजित पदों हेतु शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17-10-2008 द्वारा दिनांक 1-1-2006 से लागू करने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17-10-2008 द्वारा राजकीय कर्मचारियों के लिए 1-1-2006 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में जो वेतनमान उक्त इकाई में है, उनको उक्त शासनादेश के संलग्नक-1 के कॉलम-2 के अनुसार वर्तमान वेतनमान के संलग्नक कॉलम-2 के अनुसार वेतन बैंड व 5 के अनुसार ग्रेड पे में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- शासनादेश संख्या 395/XXVII/(7)/2008 दिनांक 17-10-2008 के प्राविधानों तथा इसके विषय में समय-समय पर निर्गत स्पष्टीकरणों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान देय होंगे तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 262/XXVII/(7)/2009 दिनांक 27-8-2009 की शर्तें एवं प्रतिबन्ध भी यथावत् लागू होंगे।

2- उक्तानुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय स्वयं की वित्तीय स्थिति के अनुरूप लिया जायेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं की जाएगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2602/XXVII(7)/2010 दिनांक 10 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस० राज०)

प्रमुख सचिव ।

सं० १५७ (१) / IV(२)-श०वि०-१०, तद॒दिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
2. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस शासनादेश को उत्तराखण्ड की वैबसाईट में सम्मिलित करने का कष्ट करें ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(निधिमणि त्रिपाठी)

अपर सचिव ।